

पाकिस्तान को भारत ने लगाई फटकार

► पाक के हालात पर है हमारी पूरी नजर : विदेश मंत्रालय

► पाकिस्तान मीडिया फर्जी खबरें फैला रहा

नई दिल्ली 09 जून. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है.

भारत ने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान फर्जी वीडियो के जरिये अपनी विफलताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं से लोगों का ध्यान भटकाने की विफल कोशिश में जुटा है. विदेश मंत्रालय के



प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब में कहा कि इस संदर्भ में हम पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का सिलसिला लगातार देख रहे हैं. यह अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का एक हताशापूर्ण प्रयास है.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस

बर्बरता की खबरें हैं जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गये हैं और कई अन्य घायल हुए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरायेगा.

यह विरोध-प्रदर्शन हाल के वर्षों में इलाके में हुई सबसे घातक अशांति के एक दिन बाद हो रहा है जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं. इससे अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इलाके में और अस्थिरता का डर पैदा हो गया है. रावलकोट में जेएएससी समर्थकों के एक साथी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में इकट्ठा होने के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं. पीओके की यह अशांति 27 जुलाई को होने वाले

प्रवक्ता ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के संकल्प को दोहराया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को लेकर तनाव चरम पर है. जॉइंट आवामी एवशन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए करती है.इन्हें खत्म करने की मांग को लेकर क्षेत्र में हिंसक विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुई है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को घेरा

► आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं, यूएन में भारत

► अफगानिस्तान पर पाक के हमलों के खिलाफ समर्थन

संयुक्त राष्ट्र/न्यूयॉर्क, 10 जून. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया. भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान

द्वारा किए गए हवाई हमलों, सीमा पार गोलीबारी और आम नागरिकों की मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अफगानिस्तान के रुख का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन इन अफगानिस्तान (यूएनएएमए) और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है. भारत ने जोर देकर कहा

जयपुर में धमाके से 7 लोगों की मौत

चीखों से गूंजा जयपुर, अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग

जयपुर, 10 जून. जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. आच्यशा नगर तलाई क्षेत्र स्थित एक पटाखा गोदाम में सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई.

देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और लगातार हो रहे धमाकों से आसपास का इलाका दहल उठा. हादसे में एक बच्चे समेत



सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. प्रशासन के अनुसार मृतकों में अब्दुल वाहिद, बिलाल खान, समीर, आजीम खान उर्फ आविद और राबिल की पहचान हो चुकी है,

एक पिस्तौल, दो मैगजीन और 13 कारतूस जब्त

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने एक वाहन से विदेशी पिस्तौल बरामद की और अवैध हथियार तस्करी को नाकाम कर दिया. यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी जांच के दौरान पुलिस ने एक और पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद किये. बारामूला पुलिस और सेना की 52वीं राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीम ने चंदसुमा, कनिस्पौरा में एक मोबाइल वाहन जांच केंद्र स्थापित किया और श्रीनगर से बारामूला जा रहे एक वाहन को रोककर उसकी जांच की. तलाशी के दौरान, पुलिस ने सहयात्री के बैग से तुर्की निर्मित एक पिस्तौल बरामद की.

एलपीजी कीमत बढ़ाने और सब्सिडी घटाने से गरीबों पर बढ़ा बोझ : राहुल

नई दिल्ली, 9 जून . कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाने को सरकार का गरीब विरोधी कदम बताते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने गरीब परिवारों, महिलाओं, मजदूरों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. श्री गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि पिछले 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों और समझौतापूर्ण विदेश नीति के कारण देश ऐसी स्थिति में पहुंच



गया है जहां लाखों गरीब परिवार और महिलाएं फिर से लकड़ी के चूल्हों के धुएं पर निर्भर होने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है और पिछले तीन महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 89 रुपये बढ़ाए गए हैं.

भारत ने चीनी बार्डर पर रचा इतिहास

► जोजिला टनल का ब्रेकथू सफल

► नया अध्याय, जोजिला सुरंग ने रचा इतिहास

श्रीनगर, 10 जून. कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने वाली बहुप्रतीक्षित जोजिला टनल परियोजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है. मंगलवार को 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया.

जिसके साथ इसके खुदाई चरण का कार्य समाप्त हो गया. पश्चिमी हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के



बीच निर्मित की जा रही यह सुरंग देश की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक मानी जाती है. ब्रेकथ्रू पूरा होने के बाद अब सुरंग के भीतर शेष तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाएंगे, जिसके बाद इसे यातायात के लिए तैयार किया जाएगा. समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग दुनिया

की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब दो-तरफा सड़क सुरंगों में शामिल है। यह परियोजना ऐसे क्षेत्र में विकसित की जा रही है जहां हर वर्ष भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण आवागमन लंबे समय तक बाधित रहता है। जोजिला टनल जम्मू-कश्मीर के बालटाल क्षेत्र को लद्दाख के मीनामार्ग से जोड़ेगी.

योगदान मोदी के नेतृत्व में देश की गति और वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी

पीएम ने 12 वर्ष बिना अवकाश के लोगों की सेवा की

नई दिल्ली, 9 जून. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलब्धियों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर उनके कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि 09 जून को ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

पीएम मोदी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समांतर रूप से चरितार्थ होते देखा है. चाहे 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन



► **मोदी ने कुवैत के अमीर शेख से की चर्चा**

पश्चिम एशिया में निरंतर बदल रही सुरक्षा स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा के साथ टेलीफोन पर वहां की स्थिति पर चर्चा की तथा क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की. श्री मोदी ने कुवैत की संभ्रुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की भारत की ओर से एक बार फिर कड़ी निंदा की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संभ्रुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई. प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए तनाव कम करने, बातचीत और कुटनीति का आह्वान भी दोहराया. श्री मोदी ने कुवैत में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए अमीर को धन्यवाद दिया.

सदनों में व्यवधान लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती

नई दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सदनों का बार-बार बाधित होना और व्यवधान उत्पन्न होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है. श्री बिरला ने आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) इंडिया रीजून जॉन-2डू (नॉर्थ जॉन) का द्वितीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सदनों का बार-बार बाधित होना और व्यवधान उत्पन्न होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है. उन्होंने रेखांकित किया कि इस समस्या का समाधान विधायी संस्थाओं के भीतर राश्ट्रवादियों के अनुसूच आचरण, संवाद और सार्थक चर्चा को बढ़ावा देने में निहित है.

24 घंटे में दूसरी बार सोनिया से मिली ममता

नई दिल्ली, 9 जून. तुणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में दोनों नेता एक साथ शामिल हुई थीं। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। वहीं, सोनिया गांधी ने कथित तौर पर कहा कि कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है. मुलाकात विपक्षी इंडिया गठबंधन की उस बैठक के बाद हुई, बैठक में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, वोटर लिस्ट में बदलाव, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई.

ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक पहल

► 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से एक जुलाई से लागू होगी व्यवस्था :शिवराज

नई दिल्ली, 09 जून. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार, श्रमिक सुरक्षा और गांवों के समग्र विकास को नयी गति देने के लिए एक व्यापक वित्तीय और नीतिगत पहल की घोषणा की है.

श्री चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने जा रही नयी ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू, श्रमिक-केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए. उन्होंने



मजदूरी भुगतान समय पर हो : शिवराज

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल धन उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समय पर मजदूरी भुगतान हो. श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे और विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आये. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्ण स्वीकृति दें, ताकि एक जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके.

जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रु. आवंटित कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रु. का अंतरिम आवंटन राज्यों और केंद्र शासित

प्रदेशों को जारी किया गया. इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी. श्री चौहान ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी.

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने बनी कार्ययोजना

► ‘सहकार से समृद्धि’ विजन को गति देने पर राष्ट्रीय समिति की बैठक

नई दिल्ली, 09 जून. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए अनेक पहल कर रहा है.

इसी संघर्ष में, राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अंतिम गठित राष्ट्रीय स्तरीय नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की पहली बैठक आज नई



दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित की गई. अध्यक्षता सहकारिता मंत्रालय के सचिव एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार भट्टानी ने की. समिति ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया, जिसमें संस्थागत मजबूती, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा

राष्ट्रीय महासंघों/सहकारी संस्थाओं की समन्वित कार्रवाई, डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण, सदस्यता विस्तार तथा सहकारिता आधारित समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इफको के अध्यक्ष दिलीप संधानी, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सिद्धार्थ जैन, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा, रमन कुमार और शिव पाल सिंह, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के कुलपति, नाबार्ड के अध्यक्ष तथा मंत्रालयों, राष्ट्रीय सहकारी महासंघों, सहकारी संस्थाओं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों प्रतिनिधि उपस्थित थे.

फायरिंग केस में फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक

पटना. फायरिंग मामले में नामजद किए गए फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अदालत ने मामले को केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं. इन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी.

हम घुट-घुटकर मर जाएंगे : हाई कोर्ट

► हरियाली खत्म करने पर क्यों तुली है सरकार

► पोलो क्लब की जमीन पर केंद्र से पूछे तीखे सवाल

नई दिल्ली, 9 जून. दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमखाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लब की जमीन को अपने कब्जे में लेने की केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना पर सख्त रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं.

अदालत ने कहा कि राजधानी में हरित क्षेत्रों और खुले स्थानों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रदूषण और बढ़ती आबादी के कारण दिल्ली पहले

से ही गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि इन जमीनों का अधिग्रहण करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है और भविष्य में इन क्षेत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा. अदालत ने विशेष रूप से पोलो क्लब और जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर सरकार की योजनाओं पर स्पष्टीकरण मांगा. सुनवाई के दौरान अदालत ने चिंता जताई कि यदि इन खुले क्षेत्रों पर बड़े निर्माण कार्य किए गए तो इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली और खुले स्थानों में और कमी आ सकती

है. अदालत ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में उपलब्ध सीमित खुले स्थान लोगों को कुछ राहत प्रदान करते हैं और इनके स्वरूप में बड़े बदलाव का प्रभाव व्यापक हो सकता है. यह मामला भारतीय पोलो एसोसिएशन द्वारा दापर याचिका के बाद अदालत पहुंचा, जिसमें 20 मई 2026 को जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित भूमि का उपयोग सार्वजनिक और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाना प्रस्तावित है तथा केंद्रीय दिल्ली में उपलब्ध भूमि सीमित है.

टनल के समानांतर बनेगी नई ट्यूब टनल :जितेंद्र

नई दिल्ली, 09 जून. नई केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना की घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर एक नई दो-लेन ट्यूब टनल का निर्माण किया जाएगा.

उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बताया. एनएचआई और नितिन गडकरी का जताया आधार- जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) और केंद्रीय



सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि उधमपुर के लिए यह एक और अच्छी खबर है और नई टनल के निर्माण से चेनानी-नाशरी मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी. एनएच-44 पर यातायात प्रबंधन होगा बेहतर- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 जम्मू-कश्मीर की जीवनरेखा है और इस मार्ग पर वाहनों की संख्या

लगातार बढ़ रही है. ऐसे में मौजूदा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर नई दो-लेन ट्यूब टनल का निर्माण यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा. साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ- जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह परियोजना केवल स्थानीय निवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आवागमन करने वाले लाखों लोगों के लिए भी लाभदायक साबित होगी. नई टनल बनने के बाद यातायात का दबाव विभाजित होगा.